देश की सुरक्षा के लिए अपनाना होगा सख्त रवैया

अहिंसा सर्वोच्च, पर खतरे में सख्ती जरूरी : योगी

नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण में दिया संदेश

लखनऊ, 30 मई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण अवसर पर कहा कि जब देश सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूत होता है तो विश्व भी मित्रता का भाव रखता है.

उन्होंने कहा कि अहिंसा भारतीय जीवन का सर्वोच्च धर्म है, लेकिन जब देश और समाज की सुरक्षा पर संकट हो तो उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाना भी आवश्यक है, और भारतीय सेना यह जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी सोच और स्पष्ट लक्ष्य से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं. उन्होंने नौसेना शौर्य वाटिका को युवाओं के लिए प्रेरणास्थल बताते हुए कहा कि यहां भारतीय नौसेना के शौर्य, संघर्ष और परिस्थितियों से जूझने की जानकारी मिलेगी, जो युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि आकाश को छूने के लिए 'नभः स्पृशं दीप्तं' जैसी विराट सोच जरूरी है.

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि देशवासियों को पंचप्रण के साथ जुड़ना चाहिए और सेना के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिससे 140 करोड़ नागरिक सुरक्षित जीवन जी पाते हैं.

उन्होंने कहा कि सुरक्षा का बेहतर वातावरण ही विकास और जनकल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाता है. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति असुरक्षा और माफिया प्रभाव से प्रभावित थी, लेकिन आज प्रदेश विकास और निवेश का केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार सेना से जुड़े स्थलों और स्मारकों को बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य अधिकारियों के सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि यह परियोजना लखनऊ को देशभक्ति और सैन्य गौरव के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करेगी.

वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया से विकास की राह पर यूपी : राजनाथ

लखनऊ, 30 मई . नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के बदले हुए स्वरूप की सराहना की. उन्होंने कहा कि कभी यूपी की पहचान कानून-व्यवस्था की समस्याओं और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' जैसी छवि से जुड़ी थी, लेकिन अब राज्य विकास, निवेश और सुशासन का मॉडल बन चुका है.राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि अपराध और माफिया पर सख्त कार्रवाई से प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजना के जरिए रोजगार और आर्थिक विकास का केंद्र बन रहा है. उन्होंने नौसेना शौर्य वाटिका को देशभक्ति और सैन्य परंपरा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह स्थल युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करेगा.

सेवानिवृत से पहले मोदी से मिले नौसेना प्रमुख

नयी दिल्ली 30 मई. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सेवा निवृत होने से पहले शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नौसेना की तैयारियों तथा हिन्द महासागर की स्थिति के बारे में जानकारी दी.

नौसेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी के साथ एडमिरल त्रिपाठी की मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने 29 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात की. नौसेना प्रमुख ने 31 मई को नौसेना की कमान सौंपने से पहले प्रधानमंत्री को नौसेना की संचालन तैयारियों और हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी. इसमें समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और तेज़ी से बदलती तकनीक के प्रभाव भी शामिल थे. नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट, भविष्य के लिए तैयार और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

डिजी यात्रा 10 करोड़ के पार

नयी दिल्ली, 30 मई. दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर निर्बाध हवाई यात्रा के लिए डिजी यात्रा का इस्तेमाल 10 करोड़ को पार कर चुका है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि डिजी यात्रा ऐप आईओएस और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर 2.4 करोड़ से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है. इसने 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राओं को सक्षम बनाया है. भौतिक दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता समाप्त होने से डिजी यात्रा के जरिये हवाई अड्डों पर प्रवेश प्रक्रिया में प्रति यात्री औसत समय 15 सेकंड से घटाकर मात्र पांच सेकंड हो गया है. इससे भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिली है और भौतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी अतिरिक्त लागत एवं समय में कमी आयी है. इसके अलावा, भौतिक बोर्डिंग पास की आवश्यकता समाप्त होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है. प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, 'मैं डिजी यात्रा टीम को 10 करोड़ उपयोग के इस महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए बधाई देता हूं.

तीन लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 30 मई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के मामले में मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड, उत्तर प्रदेश के एक मनोनीत सदस्य को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 29 मई को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसकी गिरफ्तारी भी उसी दिन कर ली गयी. मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता की मां के नाम पर चल रही एक प्राइवेट फर्म के टेंडर को बिना किसी बाधा के जारी रखने के एवज में 3,00,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

युवाओं का देश और संविधान पर अटूट विश्वास

- **'कॉकरोच जनता पार्टी' पर दी पहली प्रतिक्रिया**
- **आरएसएस बोला-जेन-को लोकतंत्र पर भरोसा**

नागपुर, 30 मई . 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है.

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है और इसमें हर विचार व आवाज के लिए जगह मौजूद है. नागपुर में पत्रकारों से

बातचीत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग-अलग विचारों का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे असाधारण नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं, खासकर जेन-ं को भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.

आंबेकर ने कहा कि भारत में पारदर्शी चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत संस्थाएं मौजूद हैं, जो लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाती हैं. उनके अनुसार, 'हमारा लोकतंत्र मजबूत है और हर आवाज को जगह देने की क्षमता रखता है. उन्होंने यह भी कहा कि युवा वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आस्था रखता है और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखता है. समस्याओं का समाधान भी लोकतांत्रिक तरीकों से ही संभव है.

भारत का आतंकवाद पर सख्त रुख : जायसवाल

नई दिल्ली, 30 मई. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख को दोहराते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है जो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कायम है और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई जरूरी है.

साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए.

एक नजर में

सूर्या हत्याकांड मामले में सियासत तेज

गाजियाबाद. खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मामले में विभिन्न दलों के नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने घटना को दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि शासन-प्रशासन को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए. उन्होंने दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा देने की मांग की.वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हत्या में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के दायरे में लाकर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

वियतनाम खरीदेगा भारत से ब्रह्मोस, इंडोनेशिया के साथ डील अंतिम चरण में

नई दिल्ली. भारत के रक्षा निर्यात और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला डायलॉग में बताया कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए समझौता कर लिया है, जबकि इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी और आसियान देशों के साथ गहरे होते संबंधों को दर्शाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्नत रक्षा तकनीक का हस्तांतरण केवल भरोसे और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित होता है और भारत इसे केवल मित्र देशों के साथ साझा करता है. वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ समझौते भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और हिंद-प्रशांत रणनीति को मजबूत करते हैं. ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है, जिसकी गति मैक 3 तक है. इसे जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बी—चारों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है, जिससे इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है. भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा विकसित यह मिसाइल भारतीय रक्षा क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.वर्ष 2022 में फिलीपींस पहला विदेशी ग्राहक बना था, जिसने लगभग 37 करोड़ डॉलर में यह प्रणाली खरीदी थी. अब वियतनाम और संभावित रूप से इंडोनेशिया के जुड़ने से भारत का रक्षा निर्यात वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

आज का इतिहास

1577- मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म.
1727- फ्रांस, ब्रिटेन तथा नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए.
1759- अमेरिका के पेंसिलवेनिया प्रांत में थियेटर के सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया.
1774- भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया.
1867- बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई.
1878- जर्मनी के युद्धपोत एसएम एस ग्रोसर करफर्स्ट के डूबने से 284 लोगों की मौत.
1889- पेंसिलवेनिया प्रांत के जांसटाउन में भीषण बाढ़ से 2200 लोगों की मौत.

राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री चौधरी को दी खुली चेतावनी

सरकारी बंगला खाली करने से राबड़ी देवी का इनकार, बोलीं- 'फोर्स बुलाकर खाली करा लें'

- **अंतिम नोटिस के बाद भी आवास छोड़ने का मूड नहीं**
- **बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को किया आवंटित**

पटना , 30 मई . बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह फिलहाल आवास खाली करने के पक्ष में नहीं

हैं. दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में राबड़ी देवी से जब सरकारी आवास खाली करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संक्षिप्त लेकिन तीखा जवाब देते हुए कहा, 'फोर्स बुलाकर खाली करा लें.' उनके इस बयान को राज्य सरकार के लिए खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.हालांकि, सरकारी आवासों को लेकर पूर्व में आए न्यायिक निर्देशों के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व उपमुख्यमंत्रियों के लिए ऐसे आवासों को स्थायी रूप से बनाए रखना संभव नहीं माना गया था. राबड़ी देवी के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

अंतिम नोटिस के बाद बढ़ा विवाद

भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया था. विभाग का कहना है कि यह आवास अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, इसलिए इसे जल्द खाली किया जाना आवश्यक है. नवंबर 2025 में राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित कर दिया गया था.

दो दशक से रह रहा है लालू परिवार

10 सर्कुलर रोड स्थित यह बंगला पिछले करीब 20 वर्षों से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव परिवार का निवास रहा है. वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था. बाद में इसे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके पद के आधार पर आवंटित रखा गया.

वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली. वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने विदेशों से लाए गए जानवरों के ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी और निर्धारित नियमों के तहत पूरी की गई थीं. कोर्ट ने विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही माना और मामले में दोबारा जांच कराने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएई, ब्राजील, वेनेजुएला, चेक गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न देशों से लाए गए जानवरों का स्थानांतरण संरक्षण और पुनर्वास के उद्देश्य से किया गया था, न कि किसी व्यावसायिक लाभ के लिए.

एसआईआर एक विश्वसनीय प्रक्रिया : ज्ञानेश

- **चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकारों के सम्मेलन को संबोधित किया**

नई दिल्ली, 30 मई. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची को दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक बताया है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता को और मजबूत करने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं.

वह इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकारों के दूसरे राष्ट्रीय

सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस सम्मेलन में देशभर से आए कानूनी प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि दबाव और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता सूची की विश्वसनीयता और अधिक बढ़ी है. सम्मेलन में मतदाता सूची निर्माण, विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और मतदान एवं मतगणना व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. चुनाव आयोग ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कानूनी सलाहकारों को चुनावी प्रक्रियाओं की गहन समझ देना और संस्थागत समन्वय को मजबूत करना है.

आयोग ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में चुनाव संबंधी कानूनी मामलों में वृद्धि हुई है, इसलिए कानूनी तैयारी और बेहतर बचाव रणनीति बेहद जरूरी हो गई है. यह सम्मेलन न्यायिक चुनौतियों, कानूनी मिसालों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श का मंच भी प्रदान कर रहा है.

अफगानिस्तान में शरणार्थियों से भरा ट्रक के पलटने से 22 की मौत

काबुल. अफगानिस्तान के लघमान प्रांत के सोरखाकन इलाके में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहा एक ट्रक शनिवार सुबह पलट गया जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गयी. इस हादसे में 36 अन्य घायल हो गए. नांगरहार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रमुख, मौलवी अमीनउल्लाह शरीफ ने पज्वोक समाचार एजेंसी से कहा कि काबुल-जलालाबाद राजमार्ग पर लघमान प्रांत में एक प्रवासी वाहन के पलटने से महिलाओं एवं बच्चों सहित 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए.जिनका उपचार किया जा रहा है.

दिखावटी नहीं, असली सुधार चाहिए

- **पेपर लीक पर केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना**

नई दिल्ली, 30 मई. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समस्या की जड़ तक जाने के बजाय केवल दिखावटी कदम उठा रही है.

केजरीवाल ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए प्रश्नपत्रों को वायुसेना के विमान और बुलेटप्रूफ वाहनों से ले जाने का फैसला समाधान नहीं, बल्कि 'दिखावा' है. उन्होंने सवाल किया

कि क्या ऐसी व्यवस्थाओं से पेपर लीक रुक जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि लीक आखिर हो कहां से रहे हैं और उन कमजोरियों को दूर करना चाहिए. केजरीवाल के अनुसार, यदि नीयत सही होती तो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती पर वास्तविक काम होता.

उपलब्धि

एआई के मामले में चौथे स्थान पर भारत

भारत बना 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली, 30 मई. भारत ने वैश्विक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में बड़ी छलांग लगाते हुए जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है.

'स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026' रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है.

रिपोर्ट इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है.

इसमें कहा गया है कि डिजिटल परफॉर्मेंस के मामले में भारत ने तेज सुधार करते हुए मजबूत वैश्विक स्थिति हासिल की है.

एआई प्रदर्शन के मामले में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है और अब वह अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. यह प्रगति डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार के कारण मानी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने डिजिटल माध्यमों से लगभग 31 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया है और यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल में शामिल हो चुका है. साथ ही वैश्विक एआई उपयोगकर्ताओं में भारत की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत बताई गई है.

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरकंप्यूटिंग क्षमता और निजी निवेश अभी भी सीमित है. विशेषज्ञों का मानना है कि आगे की वृद्धि रिसर्च, निवेश और स्टार्टअप सहयोग पर निर्भर करेगी.

अमेरिकी रक्षा सब्सिडी खत्म करने की चेतावनी

सिंगापुर. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित 23वां शांग्री-ला डायलॉग में स्पष्ट किया कि अमीर देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी रक्षा सब्सिडी मुहैया कराने का युग अब समाप्त हो गया है. श्री हेगसेथ ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों और सैन्य प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक संशोधित राष्ट्रीय रक्षा रणनीति की रूपरेखा पेश की. यह रणनीति शीत युद्ध के बाद के अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मॉडल से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है. श्री हेगसेथ ने कहा, 'अमीर देशों की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा सब्सिडी देने का युग अब समाप्त हो गया है. हमें साझेदारों की जरूरत है, न कि संरक्षित राज्यों की. हम साझा जिम्मेदारी पर बने गठबंधन चाहते हैं.

तीन महीने बाद भी नहीं थमा युद्ध

वाशिंगटन, 30 मई. अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को लगभग तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. इस दौरान तीन बार युद्धविराम की घोषणा हुई, फिर भी दोनों देशों के बीच अविश्वास और रणनीतिक मतभेद बने हुए हैं.

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद हालात और गंभीर हो गए थे. संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और दोनों पक्षों को भारी सैन्य तथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में दो सप्ताह का युद्धविराम हुआ, जिसे 21 अप्रैल

को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की. अब 29 मई को दोनों देशों के राजनयिकों के बीच 60 दिनों के नए सीजफायर समझौते पर सहमति बनी है, हालांकि इस पर अंतिम मंजूरी अभी बाकी है. यही वजह है कि शांति प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. संघर्ष का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा. ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन लागत बढ़ने से वैश्विक महंगाई पर भी दबाव बढ़ा है. विकासशील देशों में महंगाई दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी इससे अछूती नहीं रहीं. इससे स्पष्ट है कि यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गया है.सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्टों के अनुसार थाड एयर डिफेंस रडार समेत कई महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन प्रभावित हुए हैं.